टीटागढ़-भेल ने शुरू की वंदे भारत स्लीपर का उत्पादन

परियोजना की लागत लगभग ?24,000 करोड़

मेक इन इंडिया के तहत ऐतिहासिक पहल

कोलकाता, 25 अप्रैल (वार्ता) देश की सेमी हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत के स्लीपर संस्करण के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड (टीआरएसएल) और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने शुक्रवार को उत्तरपारा स्थित टीआरएसएल की अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधा में समर्पित उत्पादन लाइन का शुभारंभ किया.

इस उत्पादन लाइन का उद्घाटन टीआरएसएल और भेल के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ, जिनमें टीआरएसएल के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक उमेश चौधरी तथा भेल की निदेशक बानी वर्मा प्रमुख रूप से शामिल रहे.यह परियोजना टीआरएसएल और भेल के संयुक्त उपक्रम को भारतीय रेलवे द्वारा सौंपे गए उस अनुबंध का हिस्सा है, जिसके तहत 80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेटों का डिज़ाइन और निर्माण किया जाना है. करीब 24 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में 35 वर्षों का दीर्घकालिक रखरखाव भी शामिल है. यह पहल प्रधानमंत्री के मेक इन इंडियाऔर आत्मनिर्भर भारत अभियानों के अंतर्गत रेलवे क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है.

वंदे भारत स्लीपर संस्करण न केवल भारत की पहली लंबी दूरी की सेमी हाई-स्पीड ट्रेन होगी बल्कि यह पूरी तरह से स्वदेशी डिज़ाइन, अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं और उन्नत सुरक्षा मानकों से लैस होगी. स्मार्ट ऑनबोर्ड सिस्टम, ऊर्जा कुशल संचालन और आधुनिक कोच लेआउट के साथ यह ट्रेन देशभर के यात्रियों को इंटरसिटी यात्रा का एक नया अनुभव देने के लिए तैयार की जा रही है.

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति संभव

टीआरएसएल के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक उमेश चौधरी ने कहा, ‘यह क्षण टीटागढ़ रेल सिस्टम और भेल दोनों के लिए गर्व का है. यह परियोजना दर्शाती है कि जब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र एक साझा विजन के साथ मिलकर काम करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति संभव है. उल्लेखनीय है कि उत्तरपारा स्थित यह उत्पादन सुविधा देश में एकमात्र ऐसी साइट है, जहां एक ही छत के नीचे स्टेनलेस इस्पात और एल्यूमीनियम दोनों प्रकार के कोच बनाए जा सकते हैं. वर्तमान में इसकी वार्षिक निर्माण क्षमता 300 कोच है, जिसे बढ़ाकर 850 तक ले जाने की योजना है ताकि बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके.

भारत 2047 तक 500 मिलियन टन लक्ष्य

मेक इन इंडिया को स्टील सेक्टर से बल

उद्योग मंत्री गोयल समेत मंत्रीमंडल की उपस्थिति

नई दिल्ली, 25 अप्रैल.इस्पात मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि तीन दिवसीय कार्यक्रम ‘इंडिया स्टील 2025’ में विभिन्न हितधारकों को भारतीय इस्पात क्षेत्र में मौजूद संभावनाओं, चुनौतियों और अवसरों का पता लगाने के लिए एक मंच पर लाया गया है.

यह कार्यक्रम मुंबई में 24 - 26 अप्रैल तक आयोजित किया गया है.उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया, जिसमें उन्होंने घरेलू इस्पात उत्पादन को बढ़ाने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देने के लिए भारत की रणनीतिक दृष्टि पर जोर दिया.

मंत्रालय के अनुसार, दिन के दौरान कई महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए गए. ‘विकसित भारत- भारतीय अर्थव्यवस्था में इस्पात क्षेत्र की भूमिका’ पर सत्र में वरिष्ठ नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों और उद्योग जगत के नेताओं के एक उच्च स्तरीय पैनल ने भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को साकार करने में इस्पात की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की.‘सीईओ राउंड टेबल’ की अध्यक्षता इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने की, जिसमें भारतीय इस्पात क्षेत्र के लिए मौजूदा चुनौतियों और विकास पर चर्चा की गई. ‘इंडिया-रूस राउंडटेबल’ दोनों देशों के प्रमुख हितधारकों के बीच द्विपक्षीय जुड़ाव के लिए एक रणनीतिक मंच रहा.

भारत-दक्षिण अफ्रीका ने बढ़ाया व्यापार सहयोग

भारत का निवेश 1.3 बिलियन डॉलर पार

झ2023-24 में व्यापार 19.25 बिलियन डॉलर

नई दिल्ली, 25 अप्रैल.भारत के नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रिटोरिया में 22 से 23 अप्रैल को दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापार और निवेश पर एक संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की.

व्यापक चर्चाओं में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में हाल के घटनाक्रमों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया और आगे विस्तार की विशाल अप्रयुक्त संभावनाओं को मान्यता दी. इस संबंध में, दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और पारस्परिक रूप से लाभकारी निवेश को बढ़ाने के लिए कई फोकस क्षेत्रों की पहचान की.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, जेटीसी की सह-अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के व्यापार, उद्योग और प्रतिस्पर्धा विभाग में द्विपक्षीय व्यापार संबंधों के मुख्य निदेशक मालोस लेट्सोआल व प्रिया नायर, आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य विभाग ने की. भारतीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल में दक्षिण अफ्रीका स्थित भारतीय उच्चायोग, उद्योग आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे.

भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों के अधिकारियों ने भारत-दक्षिण अफ्रीका जेडब्ल्यूजीटीआई की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लिया.

दोनों पक्षों ने फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, एमएसएमई, आभूषण निर्माण जैसे सहयोग के संभावित क्षेत्रों की समीक्षा की.

जेडब्ल्यूजीटीआई में चर्चा के मुख्य बिंदुओं में सीईओ फोरम का पुनरुद्धार, निवेश में सहयोग, कृषि उत्पादों के संबंध में बाजार पहुंच के मुद्दे, भारतीय फार्माकोपिया की मान्यता, स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली, त्वरित भुगतान प्रणाली और एकीकृत भुगतान लिंकेज प्रणाली, भारत-एसएसीयू पीटीए आदि शामिल थे ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को और बढ़ाया जा सके.

एर्गन लैब्स और ओएसपीएल ने की रणनीतिक साझेदारी

नयी दिल्ली, 25 अप्रैल (वार्ता) हल्के इलेक्ट्रिक व्हीकल पावरट्रेन टेक्नोलॉजी क्षेत्र की कंपनी एर्गन लैब्स ने आज ओमेगा सिकी प्राइवेट लिमिटेड (ओएसपीएल) के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की.दोनों कंपनियों ने यहां जारी एक संयुक्त बयान में कहा कि इस साझेदारी के तहत ओएसपीएल एर्गन की अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड पावर कन्वर्टर (आईपीसी) टेक्नोलॉजी को अपनाने वाला पहला ओईएम होगा, जिसकी शुरुआत एल5 सेगमेंट के इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स से की जाएगी. इस सहयोग को और मजबूत करते हुए, ओमेगा सिकी ने एर्गन की आईपीसी टेक्नोलॉजी के लिए 50 करोड़ रुपये का ऑर्डर दिया है.

कोकिलाबेन अस्पताल सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में शामिल

उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं के लिए वैश्विक मान्यता,30 देशों के 2,445 अस्पतालों का हुआ मूल्यांकन

मुंबई, 25 अप्रैल. कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल को न्यूज़वीक और स्टेटिस्टा की 2025 की विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की सूची में शामिल किया गया है. यह अस्पताल की नैदानिक उत्कृष्टता और रोगी-केंद्रित दृष्टिकोण के लिए एक महत्वपूर्ण मान्यता है, जो उन्नत चिकित्सा देखभाल प्रदान करने की उसकी प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है.

न्यूज़वीक और स्टेटिस्टा ने 30 देशों के 2,445 अस्पतालों का मूल्यांकन किया. यह व्यापक मूल्यांकन वैश्विक स्तर पर अस्पताल की स्थिति को दर्शाता है और आधुनिक उपचार, व्यक्तिगत देखभाल और रोगी-प्रथम दृष्टिकोण के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा मानकों को लगातार ऊपर उठाने के अस्पताल के समर्पण को उजागर करता है. कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल भारत के सर्वश्रेष्ठ रैंक वाले अस्पतालों में से एक है, जो देश में चिकित्सा उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करता है.

यह प्रतिष्ठित रैंकिंग क्लिनिकल प्रदर्शन, रोगी अनुभव, अस्पताल की गुणवत्ता और चिकित्सा पेशेवरों से प्राप्त इनपुट सहित कई महत्वपूर्ण कारकों पर आधारित है. यह वैश्विक स्वास्थ्य सेवा समुदाय के बीच एक अत्यधिक विश्वसनीय और सम्मानित मूल्यांकन है. इस सूची में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल को शामिल किया जाना, वैश्विक स्तर पर निर्धारित देखभाल और सुरक्षा के उच्चतम मानकों के प्रति अस्पताल की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

सोने-चांदी के भाव में गिरावट

देशभर में तीसरे दिन कीमतों में हलचल

नई दिल्ली, 25 अप्रैल.घरेलू सर्राफा बाजार में लगातार तीसरे दिन सोना और चांदी के भाव में मामूली गिरावट का रुख बना हुआ है.इस गिरावट के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 98,230 रुपये से लेकर 98,330 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में कारोबार कर रहा है.

इसी तरह 22 कैरेट सोना 90,040 रुपये से लेकर 90,190 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है. वहीं, चांदी के भाव में भी कमजोरी आने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में 1,00,800 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है.

दिल्ली में 24 कैरेट सोना 98,330 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 90,190 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है. वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 98,230 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 90,040 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है. इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 98,230 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 90,090 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है.

मारुति का मुनाफा 1.04% घटा

नई दिल्ली, 25 अप्रैल (वार्ता) देश की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में सकल शुद्ध मुनाफा इसके पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही के 3952.3 करोड़ रुपये के मुकाबले 1.04 प्रतिशत की गिरावट लेकर 3911.1 करोड़ रुपये रह गया.

कंपनी नेबताया कि यहां बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 की जनवरी-मार्च तिमाही में उसे 3911.1 करोड़ रुपये का सकल शुद्ध मुनाफा हुआ, जो वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के 3952.3 करोड़ रुपये से 1.04 प्रतिशत कम है.वहीं, आलोच्य अवधि में उसकी कुल आय में सात प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह 39654.8 करोड़ रुपये बढ़कर 42431.3 करोड़ रुपये हो गई. इस अवधि में उसके कुल खर्च में भी 8.6 प्रतिशत का इजाफा हुआ और यह 34624.6 करोड़ रुपये से बढ़कर 37585.5 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. एमएसआईएल ने बताया कि 31 मार्च 2025 को वित्त वर्ष 2024-25 में सकल शुद्ध मुनाफा पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के 13488.2 करोड़ रुपये के मुकाबले 7.5 प्रतिशत उछलकर 14500.2 करोड़ रुपये हो गया.

जिंसों में टिकाव

नई दिल्ली 25 अप्रैल (वार्ता) विदेशी बाजारों की तेजी के बावजूद स्थानीय स्तर पर उठाव सुस्त रहने से आज दिल्ली थोक जिंस बाजार में खाद्य तेल समेत सभी जिंसों के भाव स्थिर रहे.सरकारी वेबसाइट पर जारी खाद्यान्नों के थोक दाम इस प्रकार रहे -

दाल-दलहन- चना 5850-5950, दाल चना 6850-6950, मूंग दाल 9550-9650, उड़द दाल 9000-9100, अरहर दाल 8500-8600 रुपये प्रति क्विंटल रहे. अनाज = (भाव प्रति क्विंटल) गेहूं दड़ा 2950-3050 रुपये और चावल 3550-3650 रुपये प्रति क्विंटल रहा.

ईएसआईसी में जुड़े 15.43 लाख कर्मचारी

7.36 लाख युवा जुड़े 25 वर्ष तक

3.35 लाख महिला कर्मचारी का नामांकन

नई दिल्ली, 25 अप्रैल.कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना के तहत फरवरी में कुल 15.43 लाख नए कर्मचारी जोड़े गए हैं. इसके अलावा फरवरी, 2025 में 23,526 नए प्रतिष्ठानों को ईएसआई योजना के सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाया गया है.

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि ईएसआईसी की जारी अनंतिम पेरोल आंकड़ों के मुताबिक फरवरी, 2025 में 15.43 लाख नए कर्मचारी जोड़े गए हैं. मुताबिक फरवरी, 2025 के महीने में 23,526 नए प्रतिष्ठानों को ईएसआई योजना के सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाया गया है, जिससे अधिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई है. आंकड़ों के मुताबिक फरवरी माह के दौरान ईएसआईसी योजना के तहत जोड़े गए कुल 15.43 लाख कर्मचारियों में से 25 वर्ष तक की आयु वर्ग के 7.36 लाख कर्मचारी, जो कुल पंजीकरण का लगभग 47.7 फीसदी हैं.

समाचार विशेष

बिहार का सीएम बनना चाहते हैं चिराग पासवान!

पटना. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर संकेत दिए हैं कि वह बिहार की राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका में आना चाहते हैं. एक धार्मिक स्थल पर दर्शन के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मैं ज्यादा समय केंद्र में नहीं रहना चाहता, मेरा प्रदेश बिहार मुझे बुला रहा है. मेरे पिता केंद्र की राजनीति में ज्यादा सक्रिय रहे थे, लेकिन मेरी प्राथमिकता बिहार है और मैं ज्यादा समय तक केंद्र की राजनीति में नहीं रहना चाहता हूं.

अब उनके इस बयान पर उनकी पार्टी (एलजेपीआर) के नेताओं ने उनके बयान का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया पर वेलकम चिराग का पोस्टर भी शेयर किया है. बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से चिराग पासवान ने संकेत दिया है कि वह केंद्र की राजनीति से दूरी बनाकर राज्य में सक्रिय राजनीति की ओर लौटना चाहते हैं. चिराग पासवान के बिहार की राजनीति में फिर से सक्रिय होने के संकेत मिलते ही लोजपा के नेता खुश हैं. लोजपा (रामविलास) प्रवक्ता राजेश भट्ट ने बताया कि चिराग पासवान का बिहार के प्रति प्रतिबद्धता शुरू से रही है. यही कारण है कि उन्होंने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विजन दिया. इस विजन के जरिए उन्होंने तय किया है कि बिहार के लिए उनकी पार्टी और उन्होंने क्या रोड मैप तैयार किया है. राजेश भट्ट ने कहा कि चिराग पासवान बिहार के हित की बात शुरू से ही करते आ रहे हैं. उनकी मौजूदगी हमेशा बिहार में भी रहती है. उनका बिहार से एक अलग तरह का लगाव है.

जेडीयू ने किया फैसले का स्वागत

बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के आने के संकेत पर जेडीयू ने इसका स्वागत किया है. प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि रामविलास पासवान ने राजनीति में लंबा सार्वजनिक जीवन जिया है और विभिन्न पदों पर बैठे हैं. केंद्र की राजनीति में उनका एक महत्वपूर्ण भागीदारी रहा है. चिराग पासवान तीन बार से सांसद हैं और केंद्र में अभी मंत्री हैं. लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है.

राजस्थान में भाजपा के अंदर ही लड़ाई

डांगा के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र के बाद नागौर की राजनीति में हंगामा

जयपुर. चिकित्सा मंत्री गजेंद्रसिंह खींवसर और उनके बेटे धनंजय खींवसर की राजस्थान भाजपा की उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा के साथ तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है. बुधवार को ज्योति मिर्धा ने मंत्री गजेंद्र को इशारों-इशारों में धृतराष्ट्र तक कहा दिया था. अब इसका जवाब देते हुए चिकित्सा मंत्री के बेटे धनंजय सिंह ने एक्स पर ट्वीट करते हुए ज्योति मिर्धा पर निशाना साधा है.

धनंजय ने ट्वीट करते हुए लिखा, वेश बदला, दल का झंडा थामा, पर मन की कुटिलता अब भी वही पुरानी है. नवागमन तो हुआ है संगठन में, पर नीति-निष्ठा की राह अभी भी अनजानी है. यह दल है तप, त्याग और अनुशासन का प्रतीक, यहां स्व नहीं, समूह होता है असली संगीत. जहाँ ‘संगठन से बढ़कर कुछ नहीं होता, और‘ अटल निष्ठा हर कर्म पलता.

दरअसल खींवसर के विधायक रेवंत राम डांगा ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को एक शिकायती पत्र लिखा था. जिसके बाद से ही भाजपा के अंदर जैसे खलबली मची हुई है. पत्र में डांगा ने कहा था कि खींवसर विधानसभा में अभी भी हनुमान बेनीवाल की ही चल रही है. उसकी कोई सुन नहीं रहा. उसके बाद नागौर लकसभा सीट से भाजपा की प्रत्याशी रहीं ज्योति मिर्धा ने कहा था कि यह बेहद गंभीर विषय है. उन्होंने दवा किया था कि किसने यह पत्र लीक किया है उसका पता चल गया है, वो पार्टी का ही व्यक्ति है.

खड़गे की फ्लॉप रैली में जिला अध्यक्ष की बलि

नई दिल्ली. कांग्रेस पार्टी में ऐसे ही होता है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार के दौरे पर गए, जहां बक्सर में उनकी रैली रखी गई. उस रैली में तीन हजार कुर्सियां लगाई गईं और एक हजार लोगों के लिए खाना बनवाया गया इसके बावजूद रैली में तीन सौ लोग पहुंचे. खड़गे इससे इतने आहत हुए कि मंच पर भाषण देने खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि, ‘जो चंद लोग मुझे सुनने आए हैं उनका धन्यवाद’. इस फ्लॉप रैली के बाद कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष मनोज कुमार पांडेय को निलंबित कर दिया. सवाल है कि रैली फ्लॉप हुई तो क्या वह अकेले जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी?

राहुल गांधी ने अपने करीबी कृष्णा अलवरू को प्रभारी बनाया है. दो बार के विधायक राजेश राम, जो उसी इलाके से आते हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है. कन्हैया कुमार को चेहरा बनाया गया है, जिन्होंने हाल ही में पदयात्रा की है. बगल में सासाराम सुरक्षित सीट हैं, जहां से सांसद मनोज राम कांग्रेस के हैं. वह मीरा कुमार का क्षेत्र है. क्या इन सबकी जिम्मेदारी नहीं थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली को सफल बनाएं? कांग्रेस एक गलती तो यह कर रही है कि चुनाव से छह महीने पहले सहयोगी पार्टियों के साथ तालमेल नहीं बना रही है. अगर राजद और लेफ्ट से तालमेल बेहतर होता तो रैली बड़ी हो सकती थी.

आखिरी बक्सर के सांसद राजद के सुधाकर सिंह हैं और अगल बगल की तीन लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों के सांसद हैं. अगर कांग्रेस ने सोचा है कि सहयोगी पार्टियों को दबाव में रखना है ताकि ज्यादा सीट हासिल कर सकें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली में ज्यादा ताकत लगानी चाहिए थी. मुश्किल यह है कि कांग्रेस ने अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा कर समूचा इकोसिस्टम बिगाड़ दिया है. इस वजह से समस्या हो रही है.

विशेष | क्या इस साल भी वैसा ही दांव चलने जा रहे नीतीश कुमार?

सुशासन बाबू की विदेशों में रही चर्चा

पटना. बिहार की सियासत में दशकों से एक नाम है जिसने न सिर्फ स्थिरता दी, बल्कि बदलाव की नई इबारत भी लिखी. यह नाम किसी और व्यक्ति की नहीं बल्कि खुद नीतीश कुमार हैं. आज जब हम इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं, तो सवाल सिर्फ इतना है कि क्या सुशासन बाबू एक बार फिर इतिहास दोहराएंगे?

दरअसल, नीतीश कुमार की सियासी सफलता के पीछे दो बड़े फैसले हैं. पहला, जंगलराज का अंत और दूसरा, आधी आबादी को साथ जोड़ना. इन दोनों ट्रंप कार्ड्स ने बिहार की जातिगत राजनीति को एक नई दिशा दी, जहां न सिर्फ लोगों ने राहत की सांस ली, बल्कि महिलाओं ने पहली बार सियासी और सामाजिक मंचों पर अपनी पहचान बनानी शुरू की.

साइकिल योजना बनी नए बदलाव की नई शुरुआत- नीतीश कुमार ने 2006 में एक ऐसा फैसला लिया, जिसने बिहार की लड़कियों को पंख देने का काम किया. मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना की शुरुआत ने गांवों की बेटियों को स्कूल की दहलीज तक पहुंचाने का कां किया. इसकी वजह से स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला और पहली बार सरकार के स्कूलों में लड़कियों की उपस्थिति लड़कों के बराबर हो गई. यह योजना इतनी प्रभावशाली रही कि इसकी चर्चा अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक हुई. संयुक्त राष्ट्र ने न सिर्फ इसकी सराहना की, बल्कि जाम्बिया और माली जैसे अफ्रीकी देशों में इसे लागू भी करवाया. अमेरिका से आए एक प्रोफेसर ने योजना का ग्राउंड स्टडी कर रिपोर्ट बनाई, जिसे यूएनओ ने बेहद सकारात्मक रूप में लिया.

सिर्फ शिक्षा ही नहीं, सियासी भागीदारी में भी नितीश कुमार ने आधी आबादी को बराबर की हिस्सेदारी दी.

पोशाक योजना से स्कूलों में बढ़ा नामांकन

साल 2011 में शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना’ ने लड़कियों को स्कूल से जोड़े रखने में बड़ी भूमिका निभाई. कक्षा 9वीं से 12वीं की छात्राओं को हर साल ड्रेस के लिए आर्थिक सहायता दी गई, जो 2018-19 में बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई. इसका सीधा असर स्कूल नामांकन पर पड़ा, जहां पहले सिर्फ 33प्रतिशत लड़कियां नामांकित थीं, वहीं ये आंकड़ा 97 प्रतिशत तक पहुंच गया.